VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)/GENERAL STUDIES (Paper-III) (2219)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 1385290

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Muktendrakumar

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
Hindi

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)
GENERAL STUDIES (Paper III)

तारीख
Date
28-08-2022

केंद्र
Centre Delhi-Mukherjee Nagar

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

	महत्वपूर्ण अनुदेश उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Important Instructions** **Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISION IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)/GENERAL STUDIES (Paper-III) (2219)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. राजकोषीय नीति आय असमानता को कम करने के साथ-साथ सबसे निर्धन और अभावग्रस्त लोगों को देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Fiscal policy can be a key tool to reduce income inequality as well as make the poorest and the downtrodden a part of the country's growth story. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है किंतु यहाँ विश्व की सर्वाधिक गरीब आबादी रहती है। वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, शीर्ष 10% अमीरों की राष्ट्रीय आय में 57% की हिस्सेदारी है। इस स्थिति को सुधारने में "प्रभावी राजकोषीय नीति" सहायक हो सकती है।

राजकोषीय नीति
→ सरकार द्वारा कर एवं व्यय को प्रबंधित करने का उपकरण।
→ दो प्रकार .. • चक्रीय राजकोषीय नीति
• प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति।

संमावेशी विकास सुनिश्चित करने में राजकोषीय नीति की भूमिका :

① महामारी के दौर में प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति द्वारा सरकार को व्यय पर बढ़ावा एवं कर को थोड़ा कम करना।

② जिससे गरीब लोगों को अपनी आय का कुछ भाग बचाने में मदद मिलेगी।
उदाहरण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।

③ अप्रत्यक्ष करों पर जोर देने की बजाय प्रत्यक्ष करों पर ज्यादा फोकस देना, क्योंकि प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते है।

④ मंदी के दौर में मांग को बढ़ावा देने में सहायक, जिससे उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा एवं रोजगार सृजन होगा, जिससे निर्धनों को रोजगार मिल सकेगा।

निष्कर्ष: सरकार को वैश्विक भू-आर्थिक संकट के इस दौर में राजकोषीय नीति को बहुआयामी एवं स्पष्ट दृष्टिकोण धारित कर प्रयोग करना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना भूमि सुधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय न्यायपालिका पर बोझ को कम करने में भी काफी सहायक होगा। विस्तारपूर्वक समझाइए। साथ ही, इस संदर्भ में किए गए उपायों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Digitizing land records will go a long way in ensuring land reforms as well as lessening the burden on the Indian Judiciary. Elaborate. Also, state the measures taken in this context. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

"भू-सुधार" सुनिश्चित करना एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। भू-आलेखों का डिजिटलीकरण की दिशा में प्रभावी कदम भू-सुधारों को मजबूत करेगा।

भू-आलेखों का डिजिटलीकरण : लाभ

① आपसी विवादों को सुलझाया जा सकेगा। (भू-संबंधी)

② किसान "भू-रिकॉर्ड" रसीद जमा कर बैंकों से आसान ऋण ले सकेंगे।

③ प्रशासन के पास "भू-आलेखों" का सटीक डेटा होगा, जिससे नीति-निर्माण में सहायता मिलेगी।

④ भू-रिकॉर्ड के खोने की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

व्यापालिका को "भू-आलेखों" डिजीटीकरण से

लाभ → याचिकाओं (भू-संबंधी) पर सुनवाई करते समय स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध होंगे।

→ आपसी भू-विवादों की कमी से व्यायपालिका में मुकदमों में कमी।

वर्तमान में व्यायपालिका में 4.7 करोड़ केस लंबित है, ऐसे में यह कदम व्यायपालिका को राहत पहुँचायेगा।

डिजिटल प्रयास

→ डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण योजना।

→ स्वामित्व योजना।

→ भानुदत योजना (मध्य प्रदेश)

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूमि आलेखों का डिजिटलीकरण भूमि सुधार की दिशा में प्रभावी कदम होगा जिसे आगे "चकबंदी" इत्यादि के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सकेगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. ऐसा भी कहा जाता है कि अधिकांशतः नॉन-मेरिट सब्सिडी के लिए निधि (फंड) उपलब्ध कराने वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति, भारत में कुछ राज्यों को गंभीर राजकोषीय संकट के कगार पर धकेल रही है। इस संदर्भ में, भारत में सब्सिडी व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
It has been pointed out that competitive politics to fund mostly non-merit subsidies is pushing a few states in India to the brink of a deep fiscal crisis. In this context, discuss the need to rationalise the subsidy regime in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों में दी जाने वाली "मुफ्त की सौगात" के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई है यह राज्यों को गंभीर राजकोषीय संकट में डाल सकता है।

मुफ्त योजनाएं
- → फ्री बिजली
- → फ्री परिवहन
- → लैपटॉप, स्कूटी वितरण।

राज्यों पर राजकोषीय संकट : युक्तिसंगत बनाना

① RBI की रिपोर्ट अनुसार, राज्यों का ऋण-GDP अनुपात 31% को पार कर चुका है।

② पंजाब राज्य में यह 50% की सीमा को पार कर गया है।

③ "मौलिक संकट" का एक कारण फ्री योजनाओं को भी माना जाता है इसलिए भारतीय राज्य भी कमजोर स्थिति में हैं।

④ "फ्री योजनाओं" को पूरा करने हेतु राज्य या तो कर बढ़ाएंगे या फिर उधार लेंगे, इससे राजकोषीय संकट खड़ा होगा।

⑤ फ्री योजनाएँ, पर्यावरणीय संकट" को भी बढ़ावा दे रही है उदाहरण: मुफ्त बिजली से जल गहन फसलों को बढ़ावा मिलता है।

⑥ नागरिकों में आलस्य घर कर सकता है एवं इससे "चुनाव की पवित्रता" पर भी बुरा असर पड़ता है।

निष्कर्षत: सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। "मुफ्त की सौगात" एवं "कल्याणकारी योजनाओं" में अंतर करना बेहतर कदम होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4. सूक्ष्म-सिंचाई में कृषि को एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम में परिवर्तित करने की वृहद् क्षमता है। दिए गए कथन की प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Micro-irrigation has tremendous potential in transforming farming into a profitable and sustainable venture. Discuss the given statement in the context of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत के कई राज्य भू-जल का निष्कर्षण 100% की सीमा से अधिक कर रहे हैं, ऐसे में कृषि में 'सूक्ष्म सिंचाई' का महत्व काफी बढ़ जाता है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

- 2015 में शुरु
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
- "प्रति बूँद अधिक फसल" को बढ़ावा।
- "वाटरशेड प्रबंधन" का प्रावधान।
- किसानों को जल-अनुकूल (कम जल) फसलों को चुनने मे सहायता।

योजना से कृषि को लाभ

(1) कृषि क्षेत्र कुल भू-जल का 80%. से अधिक प्रयोग करता है, इसलिए सूक्ष्म सिंचाई भू-जल संकट को रोकने में सहायक होगा।

(2) बढ़ते वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन के दौर में इससे "स्मार्ट कृषि" को बढ़ावा मिलेगा।

(3) सूक्ष्म सिंचाई से किसानों की लागत में कमी आएगी, आय बढ़ेगी।

(4) यह "फसल विविधता" को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

(5) जल का दीर्घकालिक प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

(6) फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी।

निष्कर्षतः सूक्ष्म सिंचाई को तीव्रता, कुशलता के साथ लागू किये जाने की आवश्यकता है, कृषकों के साथ संबंधों को और मजबूत किया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. भारत के विशाल संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता को देखते हुए, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में प्रशांत महासागर के लघु विकासशील द्वीपीय देशों (PSIDS) की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Given its vast resources and technical expertise, India can play a key role in assisting the Pacific Small Island Developing States (PSIDS) in dealing with the impact of climate change. Analyse. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

'COP26' में भारत ने कई देशों के साथ मिलकर (IRIS) पहल का शुभारंभ किया, जो प्रशांत महासागर के लघु विकासशील द्वीपों को सहायता प्रदान करेगा।

PSIDS पर जलवायु परिवर्तन का

प्रभाव

→ समुद्र का बढ़ता स्तर, तटीय भाग डूबने का खतरा।

→ आबादी की आजीविका को बनाए रखने का मुद्दा

भारत के प्रयास

- CDRI
- IRES
- OWOSOG

इस प्रकार भारत PSIDS की सहायता कर अपनी स्थिति को वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करेगा, जिससे 'क्वाड' की भी मजबूती होगी एवं भारत जलवायु परिवर्तन का नेतृत्व हासिल कर सकेगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

6. हालिया "पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (DMP-MoPR)" का उद्देश्य जमीनी स्तर पर आपदा प्रत्यास्थता विकसित करना है। इस संदर्भ में, इस योजना के निर्माण के लिए उत्तरदायी तर्क की विवेचना कीजिए और इसके प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The recent "Disaster Management Plan of Ministry of Panchayati Raj (DMP–MoPR)" aims to develop disaster resilience at the grassroots level. In this context, discuss the rationale behind the formulation of the Plan and highlight its key components. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत कई प्रकार की आपदाओं का प्रतिवर्ष सामना करता है। बाढ़, सूखा, चक्रवात, इत्यादि इनमें सम्मिलित है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में मजबूत आपदा प्रबंधन नीति बेहद आवश्यक है।

पंचायती राज की आपदा प्रबंधन योजना

↳ इस योजना के द्वारा स्थानीय निकायों को आपदा प्रबंधन में भागीदार बनाया गया है।

निर्माण के लिए उत्तरदायी तर्क

(1) स्थानीय निकाय (पंचायत) आपदा के प्रति प्रथम प्रतिक्रिया निकाय होता है।

(2) "आपदा प्रबंधन" को विकेंद्रीकृत करना।

(3) 'आपदा' के प्रति लोगों को जागरूक बनाना एवं प्रतिक्रियाशील बनाना।

(4) पंचायती राज को सशक्त बनाना।

(संदर्भ फ्रेमवर्क)

प्रमुख घटक

- प्रत्येक गाँव हेतु "आपदा प्रबंधन योजना"
- कार्यान्वयन हेतु एक निकाय की स्थापना।
- योजना निर्माण निकाय में "सुभेद्य लोगों" का प्रतिनिधित्व।
- जागरूकता फैलाने एवं क्षमता विकास पर जोर।

निष्कर्षतः पंचायती राज मंत्रालय का यह कदम भारत को "आपदा प्रत्यास्थ भारत" बनाने में मदद करेगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उभरती एवं विघटनकारी प्रौद्योगिकियों (EDT) के उपयोग से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा संबंधी निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the internal security implications emanating from the use of Emerging And Disruptive Technologies (EDT) by state and non-state actors. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वर्तमान में नवीन प्रौद्योगिकियों का उद्भव नई चुनौतियों को जन्म दे रहा है जिस पर सिडनी डॉयलॉग में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ध्यान पर प्रकाश डाला गया है।

EDT
→ ब्लॉकचेन तकनीक
→ कृत्रिम बुद्धिमत्ता
→ साइबर स्पेस
→ डार्क वेब

राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा "EDT" के उपयोग से उत्पन्न चुनौतियाँ / निहितार्थ

(1) "साइबर युद्ध" को बढ़ावा।
उदाहरण: (सोलर विंड अटैक) (US)

(2) E-DT का प्रयोग कर धन शोधन एवं ड्रग तस्करी को बढ़ावा

(3) आतंकवादियों द्वारा ऑनलाइन भर्ती।

(4) ~~[illegible]~~ मानव तस्करी एवं अवैध वन्य जीव व्यापार के लिए 'E-DT' का प्रयोग। (WWF)

(5) 'फेक न्यूज' को बढ़ावा देकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना।

(6) राज्यों के 'महत्वपूर्ण अवसंरचना' को आक्रान्त करना, उदाहरण: मुंबई मे 'ब्लैक आउट'

निष्कर्षत: भारत को E-DT से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए "मजबूत साइबर फोर्स" एवं एजेंसियों के मध्य समन्वय बनाकर इसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने में भारत द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Identify the impediments faced by India in boosting its defence exports. Also, discuss the steps taken by the government in this regard. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने में कई बाधाएं उपस्थित हैं

बाधाएं

- हथियारों की डिजाइन व विकास क्षमता का अभाव।
- निजी क्षेत्र की कम भागीदारी।
- R&D पर कम खर्च (0.7%)
- प्रशासनिक बाधाएं
- "रक्षा उत्पादों" की कुशल ब्रांडिंग का अभाव।

सरकारी कदम

- रक्षा उत्पादन एवं निर्यात नीति 2020
  2025 तक 5 बिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
  भारत को हथियारों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने हेतु
- प्रौद्योगिकी विकास फंड (DRDO)
- दो रक्षा औद्योगिक गलियारे (UP, तमिलनाडु)
- रक्षा क्षेत्र : FDI (74%)

निष्कर्ष : ये प्रयास असर दिखाने लगे हैं, वित्त वर्ष 2022 में रक्षा निर्यात 13000 करोड़ रहा, इसे आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. अंतरिक्ष मलबे से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस खतरे से निपटने के लिए हाल के दिनों में की गई पहलों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the multiple issues associated with space debris. Also, state the initiatives taken in recent times to tackle this menace. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अंतरिक्ष की तीव्र प्रतिस्पर्धा ने व्यापक अंतरिक्ष मलबे को जन्म दिया है जो काफी चिंताजनक है।

मुद्दे

(1) कैसलर सिंड्रोम

(2) "सोलर स्टॉर्म" का प्रभाव स्पेस ऑब्जेक्ट पर पड़ सकता है।

(3) अंतरिक्ष यात्रियों को क्षति का मुद्दा।

(4) लगातार 'सूचना प्रवाह' स्पेस उपग्रह से बनाए रखने का मुद्दा।

(5) अंतरिक्ष मलबे को प्रबंधित करने के लिए कोई प्लेटफार्म एवं मजबूत अंतर्राष्ट्रीय नीति नहीं है।

पहल

→ भारत में ISRO का 'प्रोजेक्ट नेत्रा'

→ नासा की कई पहलें।

→ अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति।

आगे की राह

* अंतरिक्ष मलबे को वापस धरती पर लाने हेतु नवीन तकनीकों का विकास।

* 'अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय' की ओर प्रयास करना।

* अंतरिक्ष मलबे पर लगातार निगरानी कायम रखना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. भारत में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) को अपनाने से उपभोक्ताओं के लिए ई-कॉमर्स के अधिक समावेशी और सुलभ बनने की संभावना है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
The adoption of Open Network for Digital Commerce (ONDC) in India is expected to make e-commerce more inclusive and accessible for consumers. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

ई-कॉमर्स को समावेशी एवं सरल बनाने के लिए भारत सरकार ONDC प्लेटफॉर्म लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है।

ONDC
→ कई कंपनियों का एक प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति।
→ ग्राहक एक ही प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर खरीद कर सकते हैं

लाभ : कार्टेलाइजेशन को रोका जा सकेगा।

(2) एकाधिकार का हटना एवं प्रतिस्पर्धा का विकास ई-कॉमर्स में हो सकेगा।

(3) ग्राहकों को सस्ती वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्राप्त होगी।

(4) छोटे विक्रेताओं की सुरक्षा।

(5) अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास।

निष्कर्ष: ONDC ई-कॉमर्स को प्रभावी एवं समावेशी बनाने की दिशा में सार्थक कदम है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidates must not write on this margin

11. यद्यपि, हाल ही में "क्षतिकारक" सरकारी मत्स्यन सब्सिडी को रोकने के लिए डब्ल्यू. टी. ओ. के मंच पर एक समझौते पर सहमति बनी है, तथापि, भारत द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं से पता चलता है कि इस मामले में और अधिक वार्ता किए जाने की आवश्यकता होगी। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
While an agreement was recently reached at the WTO on a deal to curb "harmful" government fisheries subsidies, certain concerns raised by India suggests that the matter will require further negotiations. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में, WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की बैठक 'जेनेवा' में संपन्न हुई जिसमे मत्स्यन सब्सिडीयों समझौते को अपनाया गया है।

मत्स्यन सब्सिडी समझौते के प्रावधान

(1) अवैध, असूचित व हानिकारक मत्स्यन सब्सिडी पर रोक।

(2) विकासशील देशों को इसे अपनाने हेतु कुछ समय की राहत दी गई है।

(3) यह समझौता '4 वर्षीय' है।

(4) 'समुद्री मत्स्यन स्टॉक' को सतत बनाने पर जोर।

(5) सरकारों को जवाबदेह बनाये जाने का प्रावधान।

लाभ

→ FAO के अनुसार वैश्विक समुद्री मत्स्यन स्टॉक का 90% या तो दोहन हो चुका है या खत्म होने की कगार पर है।

→ ऐसे में यह समझौता "SDG14" को प्राप्त करने में सहायता करेगा।

→ चीन जैसे अवैध मात्स्यिकी को रोकने में सहायक होगा।

→ "बॉटम ट्रालिंग" को रोकने में सहायक।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत हेतु उभरती चिंताएं

(1) इस समझौते में "विशेष एवं विभेदित उपाय" की उपेक्षा की गई है।

(2) यह समझौता भारत के गरीब मछुआरों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है क्योंकि कई बार समीप मछली न मिलने पर वे दूसरे क्षेत्रों में जाकर मत्स्यन पकड़ते हैं।

(3) श्रीलंका के साथ मछली पकड़ने के मुद्दे पर भारत पर दबाव बढ़ सकता है।

निष्कर्षतः, यह समझौता समुद्री (पारिस्थितिकी) मत्स्यन तंत्र को सतत बनाने में सहायक हो सकता है, भारत को अपने मुद्दों को विकासशील देशों के साथ मिलकर प्रभावी रूप से WTO के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

12. सड़क निर्माण क्षेत्रक में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) से जुड़े लाभों के बावजूद, विभिन्न कारणों से इसमें रुचि कम हुई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Despite the advantages that are associated with the hybrid annuity model (HAM) in the road construction sector, the interest in it has moderated due to various reasons. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

LPG सुधारों के बाद से सरकार ने निजी क्षेत्र की क्षमता को पहचाना है, तथा 'PPP' मॉडल का प्रयोग करने का प्रमाण है, जिसमें "HAM" मॉडल एक प्रमुख घटक है।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

- सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी
- परियोजना की शुरुआत में सरकार लागत का 40%. निजी कंपनी को देती है।
- बाकी 60%. परियोजना के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है।

सड़क निर्माण में HAM के लाभ

① 'कोविड-19' महामारी के संकट ने सरकार की राजकोषीय स्थिति को कमजोर बनाया है, ऐसे में HAM मॉडल सरकार की प्राथमिकताओं एवं सड़क निर्माण आवश्यकता को पूरा करने में सहायक है।

② यह मॉडल "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" के अनुकूल है।

③ इससे निजी क्षेत्र की तकनीकी कुशलताओं से सड़क निर्माण डिजाइन की गुणवत्ता बढ़ती है, जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक है। ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

HAM में रुचि कम होने का कारण

विभिन्न लाभों के बावजूद वर्तमान में यह मॉडल चुनौतियों से जूझ रहा है

① परियोजना के लागू होने तक अत्यधिक कागजी कार्यवाही'

② अक्षम विवाद समाधान तंत्र'

③ सरकार की निजी क्षेत्र को आकर्षित करने की कम क्षमता।

④ निजी क्षेत्र विशेषकर लाभ के लिए कार्य करता है, जिससे लोगों पर ज्यादा शुल्क भार' डाला जाता है।

निष्कर्षतः "HAM" मॉडल की चुनौतियों को सटीकता एवं सतर्कता से हल कर नया रूप देने की आवश्यकता है, इसी के साथ अन्य मॉडलों पर भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

13. मौजूदा एम. एस. पी. खरीद व्यवस्था न तो आर्थिक दृष्टि से और न ही कृषि-पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय है। सविस्तार वर्णन कीजिए। साथ ही, मौजूदा एम. एस. पी. व्यवस्था में सुधार के लिए अपनाए जा सकने वाले वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The existing MSP procurement regime is neither economically nor agro-ecologically sustainable. Elaborate. Also, evaluate the alternative approaches that can be adopted to improve the existing MSP regime. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सरकार द्वारा किसानो को आयसुरक्षा की दृष्टि से फसल बोने के पहले 23 फसलों हेतु एक "न्यूनतम मूल्य" घोषित किया जाता है, जिसे MSP कहा जाता है। हालाँकि यह कई मुद्दों के चलते विवादों में घिरा रहता है।

आर्थिक मुद्दा : MSP

→ यह किसानो की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।

→ इसके कारण किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक नही पहुँच पाते, आज भी कृषिनिर्यात की हिस्सेदारी मात्र 2.5% है।

↳ "शांता कुमार समिति" के अनुसार MSP का लाभ केवल 6% किसानों को ही मिल पाता है।

↳ सरकार पर सब्सिडी का बढ़ता बोझ (प्र.) एवं फसलों की बरबादी।

कृषि-पारिस्थितिक मुद्दा

- जल-गहन फसलों गेहूं एवं चावल की वरीयता।
- कृषि क्षेत्र में भू-जल का अत्य. प्रयोग।
- चावल खेती से मीथेन (CH_4) का उत्सर्जन।
- पराली जलाने से पर्यावरणीय संकट।
- मृदा की उर्वरता की क्षति।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वैकल्पिक नीति: सुधार हेतु:

1. MSP का तर्कसंगतीकरण।
2. 'शांता कुमार समिति' की सिफारिशें लागू करना।
3. 'फसल विविधीकरण' का प्रावधान करके MSP को मजबूत बनाना।
4. 'मोटा अनाज' की ब्रांडिंग कर MSP को तर्कसंगत करना।
5. FCI को मजबूत एवं नवाचारी बनाना।
6. किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने में सक्षम बनाना।

जैसा कि तिरुवल्लुवर ने किसानों की महत्ता पर प्रकाश डाला है, को देखते हुए किसानों को मजबूत बनाने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्वास्थ्य को सतत बनाने की प्रयासों की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

14. यह तर्क दिया जा रहा है कि भारत गोदामों में खाद्यान्नों की अधिकता से जूझ रहा है। भारत की मौजूदा बफर स्टॉक नीति को ध्यान में रखते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
It is being argued that India is struggling with overflowing foodgrains in warehouses. Discuss the statement in view of the existing buffer stock policy of India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत एक 'कृषि प्रधान' देश है तथा कुल आबादी का 68.8% गाँवों में निवास करता है, जिनमें से अधिकांश कृषि पर निर्भर है (49%), इसी के चलते FCI को 'बफर स्टॉक नीति' बनाकर चलना पड़ता है।

बफर स्टॉक नीति
- → MSP पर फसलों की खरीद।
- → 'खाद्य वितरण प्रणाली' हेतु आवश्यक। (65% जनसंख्या)
- → इसी के साथ बाजार हस्तक्षेप योजना, खुला बाजार बिक्री योजना हेतु भी FCI बफर स्टॉक को बनाए रखता है।

लाभ

(1) किसानों को आय सुरक्षा।

(2) 50% शहरी आबादी एवं 75% गाँव आबादी को सब्सिडीयुक्त अनाज की उपलब्धता।

(3) 'अकाल' जैसी परिस्थितियों से निपटने में सहायक।

(4) खाद्यमुद्रास्फीति को लक्षित करने में सहायक।

भारतीय खाद्य गोदाम

- केंद्र एवं राज्य दोनों में उपस्थित।
- केंद्रीय खाद्य भंडारण एवं राज्यों की संयुक्त भंडारण क्षमता लगभग 600 मीलियन मीट्रिकटन" है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

गोदामों में खाद्यान्नों की अधिकता

① 'MSP प्रणाली' के कारण खाद्यान्नों की अनावश्यक खरीद करनी पड़ती है।

② इससे अनाज की बर्बादी को बढ़ावा मिलता है।

③ "अक्षम गोदाम क्षमता" भी प्रमुख एक कारण।

④ 'खाद्य प्रबंधन प्रणाली' कुशल व नवाचारी नहीं है।

आगे की राह:

* भंडारण पर "शांता कुमार समिति" की सिफारिशें लागू करना।
* भंडारण क्षमता हेतु "PPPP मॉडल" अपनाए जाने की आवश्यकता।
* MSP को तर्कसंगत बनाया जाए।
* 'कृषि निर्यात' को बढ़ावा, 50 B डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाये जाने की आवश्यकता।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. हाल ही में, सरकार ने सभी पत्तनों (पोर्ट्स) को वर्ष 2047 तक स्वयं को 'मेगा पोर्ट्स' के रूप में विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देश दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में, पत्तनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और साथ ही, भारत की ब्लू इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Recently, the government has asked all ports to prepare a master plan in order to become 'mega ports' by 2047. In light of this, discuss the challenges faced by ports and suggest remedial measures in order to propel India's blue economy. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में 12 प्रमुख एवं 200 छोटे बंदरगाह है, जिनके द्वारा कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% से अधिक व्यापार होता है। सरकार इन बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाकर कुशल, सतत एवं मजबूत बनाने पर कार्य कर रही है।

सरकारी प्रयास:

① मेजर पोर्टस (अथॉरिटी) बिल 2020

② भारतीय बंदरगाह अधिनियम (2020)

③ "मैरीटाइम इंडिया विजन 2030"

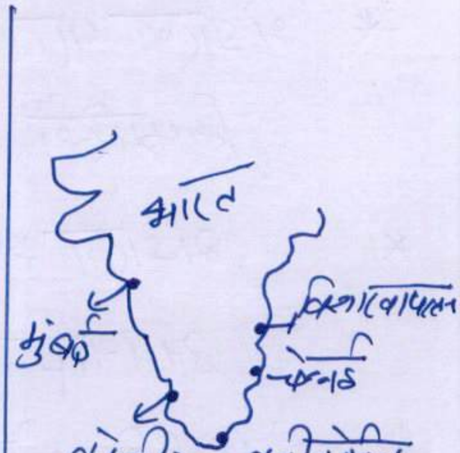

चित्र [•]: कुछ प्रमुख बंदरगाह।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पत्तनों द्वारा सामना की जाने वाली

चुनौतियाँ

- कम कार्गो हैंडलिंग क्षमता
- कुल क्षमता "1500 MMTPA" के लगभग जो काफी कम है
- बड़े कंटेनरों को हैंडल न कर पाना जिससे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को लाभ।
- डिजिटलीकरण, मशीनीकरण प्रक्रिया सरलीकरण की मंद गति।
- बंदरगाहों का प्रशासन सक्रिय न हो पाना।
- बंदरगाह तटों पर तलछट का अभाव।
- रोड, रेल, अंतर्देशीय जलमार्गों से कनेक्टिविटी का अभाव।

'न्यू इंडिया विज़न में 'ब्लू इकोनॉमी' प्रमुख 10 क्षेत्रों में से एक है जिसमें 'पत्तन' प्रमुख घटक है।

उपचारात्मक उपाय

(1) लॉजिस्टिकल लागत को कम करते हुए 'मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी' पर फोकस, इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

(2) अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं "जैसे यूरोपीय देशों से सीखना।

(3) 'केंद्र-राज्य' समन्वय की आवश्यकता।

(4) बंदरगाह तट की तलछट को हटाना।

(5) भारतीय पत्तनों की ब्रांडिंग।

PM गति शक्ति योजना, भारतमाला इस दिशा में किए गए प्रभावी कदम हैं जिन्हें उपरोक्त उपायों को अपनाकर पत्तनों का उद्धार किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

16. आय और संपदा में असमानता कार्बन असमानता में परिवर्तित हो जाती है। इस संदर्भ में, भारत के लिए कार्बन असमानता को दूर करने के महत्व पर चर्चा कीजिए और इसे प्राप्त करने के उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Inequality in income and wealth translates into carbon inequality. In this context, discuss the significance of addressing carbon inequality for India and suggest ways to achieve it. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

ऑक्सफैम इंडिया की "इनइक्वैलिटी किल्स" रिपोर्ट के अनुसार अमीरों का कार्बन उत्सर्जन गरीब आबादी की तुलना में कई गुना ज्यादा है।

भारत: आय और संपदा असमानता

* विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 10% अमीरों का राष्ट्रीय आय में 57% योगदान है इससे कार्बन असमानता को भी जन्म मिलता है

कार्बन असमानता → अमीरों की उपभोगवादी संस्कृति से ज्यादा उत्पादन को बढ़ाने से कार्बन उत्सर्जन का बढ़ना।

↓

गरीब वर्ग सिर्फ आवश्यक वस्तुओं हेतु प्रयासरत रहते हैं

कार्बन असमानता को दूर करने हेतु

भारत के लिए महत्व

① प्रस्तावना में निहित "आर्थिक न्याय" के अनुरूप।

② DPSP के "अनुच्छेद 38" "असमानता को दूर करना" के लिए आवश्यक।

③ 'पेरिस समझौते' के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक: 2030 तक 45% कार्बन उत्सर्जन कम करना।

④ वायु प्रदूषण को दूर करने हेतु, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में भारत 5वाँ सर्वाधिक प्रदूषित राष्ट्र।

⑤ 'समावेशी विकास' एवं 'हरित अर्थव्यवस्था' को प्राप्त करने के लिए आवश्यक।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उपाय

- "वस्तुओं की कार्बन तीव्रता" को मापकर एवं आय स्तर को देखते हुए कर लगाना।
- "ग्रीनपीसइंडिया" जैसे NGOs की सहायता से अमीर वर्ग में कार्बन उत्सर्जन के प्रति जागरूकता फैलाना।
- यदि किसी घर में 3 गाड़ियाँ हों तो 4th गाड़ी आवश्यक रूप से इलेक्ट्रिक हो।
- "निर्धारित आयस्तर" वाले परिवारों हेतु "सोलर पैनल" को अनिवार्य बनाना।

निष्कर्षतः "हम समाधान का हिस्सा हैं" के सिद्धांत को लेते हुए सभी वर्गों को, विशेषकर अमीर वर्ग को कार्बन असमानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. भारत में पिछले एक दशक के दौरान भूस्खलन की बढ़ती और नियमित घटनाओं के बावजूद, विकास के प्रमुख प्रतिमानों (पैरडाइम) में कोई मुख्य संशोधन नहीं किया गया है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Despite increased and regular occurrences of landslides over the past decade in India, the dominant development paradigm has largely not been modified. Examine. (Answer in 250 words)15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12% भाग भू-स्खलन से प्रभावित है। हाल ही में, मणिपुर के नोनी जिले में भयानक भू-स्खलन देखा गया।

इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष भू-स्खलन से प्रभावित होती है, जिसमें व्यापक जान-माल का नुकसान होता है।

विकास के प्रतिमान : भूस्खलन

① भू-स्खलन संवेदनशील क्षेत्रों में बाँध, सड़क, होटल

इत्यादि बनाना।

② विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन का समावेशन न किया जाना, जो पहाड़ी क्षेत्रों में भू-स्खलन का कारण बनता है।

③ हिमालयी क्षेत्रों में अनियंत्रित पर्यटन को बढ़ावा।

④ भू-स्खलन प्रभावी क्षेत्रों में विकास योजनाओं के चलते वनोन्मूलन।

हालाँकि सरकार भू-स्खलन को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

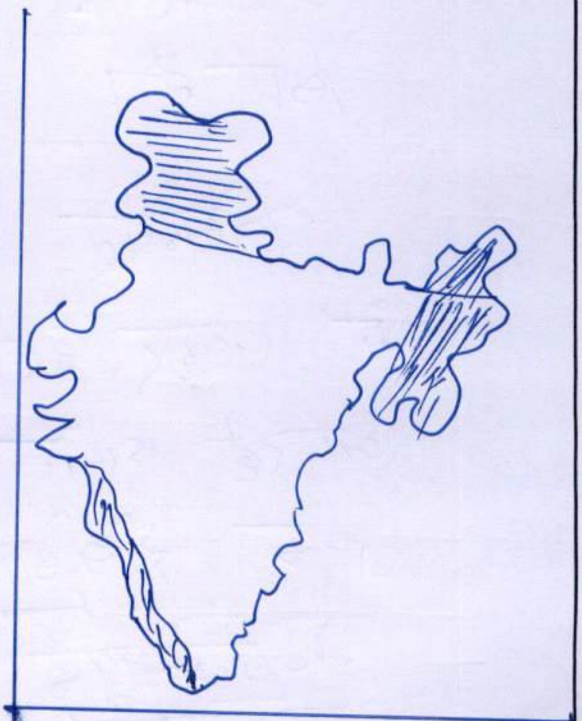

चित्र: भू-स्खलन प्रभावी क्षेत्र।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

प्रयास

* GSI ने भू-स्खलन संवेदनशील क्षेत्रों का 'मानचित्र' तैयार किया है।
* "राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष" बनाया गया है।
* पर्यटन मं० ने संधारणीय पर्यटन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति एवं रणनीति मसौदा तैयार किया है।
* NDMA ने भू-स्खलन से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है।

निष्कर्ष: भू-स्खलन से निपटने में सरकार द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं, इनसे निपटने के लिए एक 'दीर्घकालिक दृष्टिकोण' लेकर 'सेंडाई फ्रेमवर्क' का पालन किया जाना सहायक हो सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

18. राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ वैध सीमा-पार प्रवाह को संतुलित करने के लिए भारत को एक स्मार्ट सीमा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों को रेखांकित कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

India needs a smart border management system to balance legitimate cross border flows with national security interests. Discuss. Also, highlight the initiatives taken by the government in this regard. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत की 15,200 कि.मी. लंबी स्थल सीमा रेखा है, जिसका कुशल प्रबंधन एक जटिल कार्य है, जो भारत की 'सुरक्षा प्रणाली' के लिए बेहद आवश्यक है।

वैध-सीमा प्रवाह
- व्यापार
- यात्रियों की आवाजाही।

अवैध-सीमा प्रवाह
- ड्रग्स तस्करी।
- हथियार व्यापार (अवैध)।
- मानव तस्करी।
- आतंकवाद
- अवैध प्रवासन इत्यादि।

स्मार्ट सीमा
प्रबंधन प्रणाली

* इसमें तकनीकी
के प्रयोग
पर जोर
दिया जाता है,
जैसे: ग्राउंड सेंसर
ड्रोन इत्यादि।

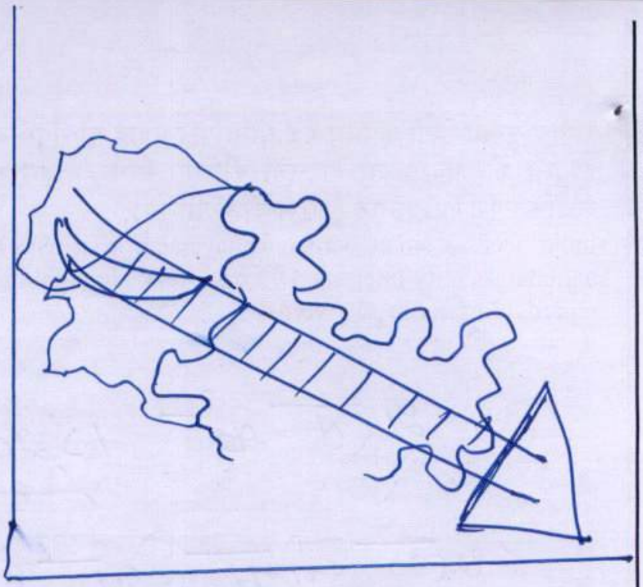

चित्र: गोल्डन ट्रायंगल
व गोल्डन
क्रीसेंट के
बीच ड्रग
तस्करी

आवश्यकता

→ म्यांमार के साथ 16Km
मुक्त आवागमन व्यवस्था
की निगरानी हेतु।

→ 'तस्करी' को
ठीक करने हेतु

→ बांग्लादेश जैसे देशों
के साथ 'शिथिल सीमा'

→ 'सैन्य बलों'
की क्षमता बढ़ाने
व 'क्षति' को कम करने हेतु।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सरकारी पहलें :

* बांग्लादेश बॉर्डर हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड-QIT का संचालन, इससे 'रिवरीन सीमा' से निपटने में सहायता मिलेगी।

* "CIBMS" का संचालन कर पाकिस्तान बॉर्डर का प्रबंधन।

* "सुरक्षा बलों" को नवीनतम तकनीकों की सुविधा कराया गया है।

निष्कर्षतः 'स्मार्ट सीमा' भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने में 'मील का पत्थर' साबित हो सकती है। इसके अलावा प्रशासन व एजेंसियों के मध्य समन्वय बनाना भी अति आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

19. वैश्वीकरण और धन शोधन के बीच संबंध स्थापित करते हुए, इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई पहलों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Establishing linkages between globalisation and money laundering, discuss the initiatives taken at the national and international levels to combat it. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

IMF की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक GDP का लगभग 5% मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, इसमें वैश्वीकरण ने भी बढ़ावा दिया है।

वैश्वीकरण और धन शोधन: संबंध

* वैश्वीकरण ने यात्राओं को आसान कर दिया है, जिससे मनी-लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिला है।
* वैश्वीकरण ने तकनीकी की आसान पहुँच सुनिश्चित की है, जिसका प्रयोग अपराधी मनी लॉन्ड्रिंग हेतु करते हैं जैसे डार्क वेब (द वर्ल्ड इन्टरनेट) एवं ब्लॉकचेन तकनीक (क्रिप्टोकरेंसी)

* वैश्वीकरण से अपराधी भागने छिपने (दूसरे देशों में) में सक्षम हुए हैं।

* वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय मनी-लॉन्ड्रिंग जाल को फैलाया है, जिससे निपटना किसी एक देश के बस की बात नहीं।

* राउंड ट्रिपिंग।

धन शोधन निपटने हेतु

राष्ट्रीय पहल
- PMLA 2002
  - जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है "विजय मंडल चौधरी वाद"
- ED की स्थापना, NIA की स्थापना।
- वित्तीय आसूचना इकाई (वित्त मंत्रालय)
- FEMA 1999

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अंतर्राष्ट्रीय पहलें

→ "FATF" की स्थापना जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए राष्ट्रों को सहायता प्रदान करता है।

→ वियना अभिसमय

→ UN द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किए गए हैं।

निष्कर्षतः मनी-लॉन्ड्रिंग एक बहुआयामी अपराध है, जिसे निपटने के लिए उदार एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत इस दिशा में मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों को लागू कर सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

20. ऐसे तर्क दिए गए हैं कि भारत को बाह्य अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में अपनी कुछ पुरानी धारणाओं की समीक्षा करने और नए वैश्विक मानदंडों के विकास में योगदान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

There have been arguments that India needs to review some of its past assumptions about the nature of outer space and contribute to the development of new global norms. In this context, analyse India's stand in relation to the Artemis Accords. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वर्तमान विश्व "अंतरिक्ष दौड़" में लगा हुआ है, जिसमें NASA सबसे आगे है, जो 'आर्टेमिस मिशन' को लॉन्च करने वाला है।

आर्टेमिस मिशन

- चंद्रमा पर पहली महिला को भेजना
- भविष्य में मंगल पर मानव को भेजना।
- चंद्रमा पर अन्वेषण करना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आर्टेमिस मिशन और भारत

→ भारत इसका पार्ट नहीं है।

→ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि हैं सदस्य।

→ भारत का इसमें शामिल न होना अंतर्मुखी दृष्टिकोण दर्शाता है।

पुरानी धारणाएँ

* क्षमताओं को स्थापित करना
* अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग
* आपसी सहयोग जैसे लूनार मिशन'

नए वैश्विक मानदंड

* ऐसा माना जा रहा है कि NASA और चीनी स्पेस एजेंसी चंद्रमा के संसाधनों को प्राप्त करने की दौड़ में है।

* यह ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक हो सकता है।

* ऐसे में भारत को सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है।

निष्कर्षतः बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) का पालन करते हुए भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में और सक्रिय होने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK